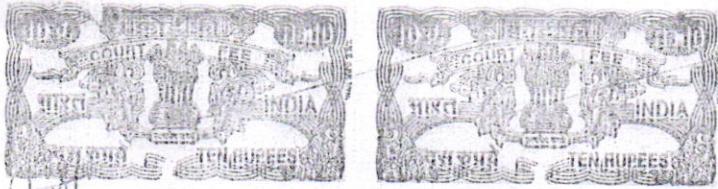


मालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0



श्री राधाराम
द्वादश दृष्टि
१२.२.१३

हीरालाल शुक्ला तबय श्री अवधशरण शुक्ला

R-779-III/13

सीतासरण शुक्ला तबय श्री जग्नुना प्रसाद शुक्ला

दोनो निवासी गाम नईहा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

२६.२.१३

3. श्रीमती सुनैना देवी पुत्री श्रीमसेन निवासी फाफर मुकाम नईहा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0
4. जगदीश प्रसाद शुक्ला तबय रघुनाथ प्रसाद शुक्ला उम्र ७० वर्ष निवासी गाम नईहा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 ——निगरानीकर्ता/आतेदकेगण

बनाम्

1. [तारा प्रसाद शुक्ला तबय श्री सुनैना प्रसाद शुक्ला मृत्यु]

तारा प्रसाद के वारिष्ठान —

1.अ. कूलमती विवाह पत्नी रव0 तारा प्रसाद शुक्ला उम्र ४५ वर्ष

1.ब. महेन्द्र प्रसाद तबय शुक्ला तबय रव0 तारा प्रसाद शुक्ला उम्र ६५ वर्ष

1.स. सबत शुक्ला तबय रव0 तारा प्रसाद शुक्ला उम्र ६। वर्ष

1.द. संतोष शुक्ला तबय रव0 तारा प्रसाद शुक्ला उम्र ५५ वर्ष

1.इ. प्रमोद शुक्ला तबय रव0 तारा प्रसाद शुक्ला उम्र ४८ वर्ष

सभी निवासी गाम नईहा पोर्ट सुकुलगवां तहसील गुढ़ जिला रीवा

(म0प्र0)

2- परीकर्ता अपा देवी पुत्री श्रीमसेन 3- मानवाना तारा प्रसाद शुक्ला मृत्यु

3- मानवाना के वारिष्ठान —

3.अ. मानवती शुक्ला विवाह पत्नी रव0 मानवाना उम्र ७५ वर्ष

3.ब. यकेश शुक्ला तबय रव0 मानवाना उम्र ३६ वर्ष

दोनों निवासी गाम नईहा पोर्ट सुकुलगवां तहसील गुढ़ जिला रीवा

(म0प्र0)

गया

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व

संहिता 1959 ई0 नियन्त्रक आदेश दि. २४/१/१३
नियन्त्रक अपा श्रीमसेन, रीवा ५८४४०-११२४/८५४०/८५४०
तारा प्रसाद शुक्ला १०९९/८५४०/११-१२, -२

राजस्व मण्डल, गङ्घाप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

नियरानी 779-तीन/2013

जिला रीवा

हीरालाल शुक्ला आदि

विरुद्ध

तारा प्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10) -7-2018	<p>आवेदक द्वारा यह नियरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1124/अपील/2005-06 नया प्रकरण क्रमांक 1099/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 28-1-2013 के विरुद्ध नों प्र० ८०५० गू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण की आरे से बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 20-9-05 को विधिवत बटवारा आदेश पारित किया था जिसे अनुविधायी अधिकारी ने अपने राही पाया। यह भी तर्क किया कि सभी अनावेदकगण एवं सभी हितबद्ध पक्षकारों को रूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया गया था जिसके पश्चात सभी का नामांतरण हो गया था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा उक्त सभी विधिवत प्रश्नों की अनदेखी कर दोनों निम्न न्यायालयों के आदेश निररत करने में त्रुटि की है।</p> <p>3/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि तहसीलदार द्वारा बिना किसी के कथन लिये तथा न कथन का प्रतिपरीक्षण किये और अनावेदकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश पारित किया था। अनावेदकों द्वारा तहसीलदार के</p>	

रामक्ष आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी परन्तु उस पर एवं कानूनी बिन्दुओं पर बिना विचार किये जो आदेश पारित किया गया उसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में उचित कार्यवाही की है।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अगिलेख का अवलोकन किया। अगिलेख के अवलोकन से रपट है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के रामक्ष बटवारा/नामंतरण आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर तहसीलदार द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी की गई। अनावेदक ताराप्रसाद की ओर आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी जिसका तहसीलदार द्वारा निराकरण किया गया है अतः अनावेदक अभिभाषक का यह तर्क गान्य नहीं किया जा सकता कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। पटवारी द्वारा उभय पक्ष के गध्य रजिस्टर्ड बटवारे के आधार पर बटवारा पुल्ली तैयार की गई थी जिसपर सभी हितबद्ध पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं। इश्तहार का प्रकाशन किया गया है तथा अनावेदक की आपत्ति प्राप्त होने पर उसका निराकरण किया गया है। तहसीलदार द्वारा सभी पक्षों का अपने अपने हिस्से पर कायम पाते हुये विधि में स्थापित बटवारा नियमों के अनुसार बटवारा आदेश पारित किया था। तहसीलदार द्वारा पारित विधिक आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी गुड जिला रीवा द्वारा भी की गई है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। जहाँ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में मात्र इस आधार पर

दोनों निम्न न्यायालयों के आदेश निरस्त किये हैं कि पंचनामा तैयार नहीं किया है और न ही भूमि का बटवारा रिथर्टि अनुसार किया गया है। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि पौके की रिथर्टि के अनुसार ही बटवारा किया गया है और रामी पक्ष बटवारे में प्राप्त भूमियों पर काविज है। ऐसी रिथर्टि में अपर आयुक्त का आदेश उचित नहीं कहा जा सकता है। अपर आयुक्त द्वारा दोनों निम्न न्यायालयों के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है, जिसे रिथर्टि नहीं रखा जा सकता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 28-1-13 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार गुढ़ का आदेश दिनांक 20-9-05 एवं अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ जिला रीवा का आदेश दिनांक 31-8-06 रिथर्टि रखे जाते हैं।

पक्षकार रूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

10/1/16
 (आरो के मिश्र)
 सदस्य